

बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

26 जुलाई 2019

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

- 21

बकाया सहित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का विचार

*440 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों का विगत मार्च 2019 से वेतन भुगतान बंद है, जिससे उनके समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि दिनांक 30 अप्रैल 2019 को विभागीय अपर सचिव (निदेशक) ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सी.एफ.एम.एस. अन्तर्गत नियोजित उन शिक्षकों के वेतन भुगतान करने का निदेश दिया था, लेकिन उनकी लचर व्यवस्था के कारण अभी तक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतलायेगी कि नई व्यवस्था के तहत खंड 'क' में वर्णित नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को कब तक बकाया सहित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

पठन-पाठन नियमित

*441 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत डुमरियाघाट प्रखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय रमपुरवा की छात्र-छात्रायें पठन-पाठन से वंचित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में प्रधान शिक्षिका सहित सभी शिक्षक गायब रहते हैं, जिससे बच्चों संग अभिभावकों को इनकी मनमानी के विरोध में प्रदर्शन करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने तथा ग्रामीण बच्चे-बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए पठन-पाठन को नियमित करने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अनुदान का प्रावधान

***442 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के राजनगर में अवस्थित विश्वेश्वर सिंह कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की एक इकाई के रूप में कार्यरत है;

(ख) क्या यह सही है कि दरभंगा महाराजा के राजनगर पैलेस के एक हिस्से में इस कॉलेज का संचालन हो रहा है जो अत्यंत भव्य एवं ऐतिहासिक इमारत है;

(ग) क्या यह सही है कि इस महाविद्यालय के भवन का लगातार क्षरण हो रहा है और रख-रखाव के अभाव में कॉलेज भवन को कभी भी क्षति पहुंच सकती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कॉलेज भवन का क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु भारत सरकार की संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तकनीकी निदेश में कार्य कराने हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

बिना लाइसेंस के कोचिंग चलाने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***443 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कोचिंग संस्थानों की मनमानी और छात्रों के शोषण को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, इसके तहत कोचिंग संस्थानों को छात्रों-शिक्षकों की जानकारी के साथ शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में अभी तक कितने कोचिंग संस्थान को शिक्षा विभाग से लाइसेंस दिया गया है और कितने कोचिंग संस्थान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, फ़ैकल्टी मेम्बर की जानकारी और एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बिल्डिंग, पाठ्यक्रम, फीस के साथ प्रदूषण विभाग, फायर ब्रिगेड से एन.ओ.सी. लेना अति आवश्यक है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो बिना शिक्षा विभाग के लाइसेंस के कोचिंग चलाने वालों और दोषी पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई की गई है?

कार्रवाई कब तक

***444 श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत महुआ प्रखंड में अप्रैल 2018 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 90 प्रखंड शिक्षकों का नियोजन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि नियोजन की तिथि से लगातार ये सभी शिक्षक अपने-अपने पदस्थापित विद्यालयों में कार्यरत हैं किन्तु अभी तक इन लोगों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे इन शिक्षकों तथा उनके परिवार के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महुआ प्रखंड के प्रखंड शिक्षकों को अविलंब वेतन भुगतान करते हुए भुगतान में हुई देरी के लिए जवाबदेह अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वेतनादि की व्यवस्था

***445 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से स्वीकृत विद्यालयों की तरह निर्धारित मानक मंडल के आधार पर शिक्षक के पद सृजित नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिना पद सृजन एवं विषय शिक्षकों की नियुक्ति के ही नामांकन हो रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक मंडल के अनुसार पदों का सृजन / शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रतिमाह वेतनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है?

language:EN-IN'>(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण के साथ-साथ कमिटी गठित कर शिक्षक की नियुक्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति

*446 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों की 'सेवा-शर्त' नियमावली 2006 के आलोक में इन्हें 10 वर्ष के उपरांत प्रोन्नति का लाभ देना है;

(ख) क्या यह सही है कि इन शिक्षकों की सेवा के 12 वर्ष के उपरांत भी प्रोन्नति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है जबकि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के सात वर्ष की सेवा के बाद ही यह लाभ दे दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नाटकों का प्रचार-प्रसार

*447 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है देश भर में पटना रंगमंच (कालिदास रंगालय और प्रेमचंद रंगशाला) की अपनी पहचान है, पटना देश के उन गिने-चुने शहरों में शामिल है, जहां साल भर में 300 से अधिक नाटकों का मंचन होता है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके बावजूद पटना में रंगमंच अब भी वह हैसियत हासिल नहीं कर पाया है कि लोग टिकट लेकर नाटक देखने पहुंचें;

(ग) क्या यह सही है कि दर्शकों की तालियों की जगह सरकारी ग्रांट के भरोसे ही नाटकों का मंचन हो रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि नाटकों का प्रचार-प्रसार एवं रंगमंच में टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण रंगमंच दर्शकों से दूर होता जा रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नाटकों का प्रचार-प्रसार एवं रंगमंच को नई टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

अतिक्रमण से मुक्ति

*448 श्री संजय कुमार सिंह (मनोनीत):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत राजकीय आदर्श मॉडर्न मध्य विद्यालय, दानापुर के परिसर की चहारदीवारी को तोड़कर उसके अन्दर एक कमरे का निर्माण करके आम लोगों के बीच चाय-नाश्ता बेचकर व्यापार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित कारणों से विद्यालय के वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालय को उक्त अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

कठिनाइयों को दूर करने का विचार

*449 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, बलवन टोला, सदर छपरा का निर्माण कार्य आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा सारण प्रमंडल के ग्रुप संख्या-555-332 के द्वारा कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नव निर्मित भवन को विद्यालय प्रबंधन को आज तक हस्तगत नहीं कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय भवन को हस्तगत नहीं कराये जाने के कारण पठन-पाठन एवं शैक्षणिक सत्र के बाधित होने की संभावना है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र के हित में शीघ्र नवनिर्मित भवन को उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज, बलवन टोला, छपरा को विधिवत एवं नियमानुसार विद्यालय प्रबंधन को हस्तगत कराकर शैक्षणिक कठिनाइयों को दूर करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राशि पर रोक

***450 डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पल रहे बच्चे-बच्चियों को शिक्षित करना सरकार का दायित्व है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने दायित्व के निर्वहन के लिए राज्य में पल रहे बच्चे-बच्चियों को शिक्षित करने के लिए सरकारी एवं निजी प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय बना रखा है, जिसमें आर्थिक लेवल के आधार पर शिक्षण-कार्य सम्पन्न किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार की नजर में संचालित निजी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी की अवधि माह जून-जुलाई महीने का विद्यालय में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं से बिना पढ़ाई के शिक्षण शुल्क एवं बस भाड़े के रूप में मोटी रकम वसूली की जाती रही है, जिससे सरकार संदेह के दायरे में आ रही है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार की नजर में निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक का शिक्षण एवं अन्य शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;

(ड) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में संचालित निजी प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से गर्मी की छुट्टी के माह जून-जुलाई का शिक्षण शुल्क एवं सवारी भाड़ा के रूप में ली जाने वाली राशि पर रोक लगाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

रिक्त पदों को भरने का विचार

*451 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिव्यांग बच्चों के सामान्य स्कूलों में पढ़ने के लिए खोले गए डे-केयर सेंटर के रिसोर्स सेंटर में थेरेपिस्ट नियुक्त किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन केन्द्रों में स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सेंटर में थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के पद भरे जा चुके हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक सारे रिक्त पदों पर सरकार भरने का विचार रखती है?

कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति

*452 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सरकारी तथा संबद्धता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक (इन्टर महाविद्यालय) शिक्षण संस्थानों में नामांकन-पंजीयन-परीक्षा प्रपत्र के साथ-साथ अन्य गैर शैक्षणिक कार्य कार्यालय सहायक/लिपिक के अभाव में शिक्षकों के ही भरोसे हैं, जिससे पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित सारे कार्यों हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली के आधार पर कार्य कर रही है, जबकि विद्यालय के स्तर पर संबंधित सारे कार्य बाजार अथवा कस्बों में स्थित इन्टरनेट शॉपी/कैफे के सहारे किये जा रहे हैं, जिसके कारण किसी भी अशुद्धियों की जिम्मेवारी संस्था के प्रधान पर ही अकारण थोप दी जा रही है तथा प्रधान के साथ-साथ शिक्षकों को भी अभिभावकों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन प्रणाली हेतु सक्षम बनाते हुए कम्प्यूटर के साथ-साथ कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शोध कार्य के प्रोत्साहन की योजना

*453 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल साइंस के शोध प्रतिवेदन से यह बात सामने आई है कि विभिन्न शोध परियोजनाओं से बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक कम लाभान्वित हो रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि डॉक्टोरल फेलोशिप, सिंगल फेलोशिप विभिन्न रिसर्च प्रोग्राम्स तथा ट्यूनिंग एवं कैपिसिटी बिल्डिंग संबंधित परियोजनाओं में यहां के छात्रों एवं शिक्षकों की दो फीसदी से भी कम भागीदारी है;

(ग) क्या यह सही है कि वि.वि. स्तर पर मात्र 1.8 फीसदी शोध पर खर्च किया जाता है जिस कारण विश्वविद्यालय समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बिहार के विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार की कौन-सी योजना है?

जल जमाव से मुक्त कबतक

*454 श्री सच्चदानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सारण (छपरा) जिलान्तर्गत उच्च विद्यालय सारण का खेल मैदान वर्षों से जलमग्न है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मैदान बरसात के समय तालाब में तब्दील हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मैदान को जल जमाव से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

***455 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

कला, संस्कृति एवं युवा

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सही है कि पश्चिम चंपारण जिले के प्रखंड बगहा 1 अंतर्गत ग्राम त्रिभौनी में खेल मैदान है जिसका खाता नं.-3, खेसरा नं.-849 है जिसमें बराबर स्थानीय युवा फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं तथा टूर्नामेंट भी कराते रहते हैं; (ख) क्या यह सही है कि त्रिभौनी खेल मैदान खुला परिसर है; (ग) क्या यह सही है कि यह खेल मैदान सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में है; (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार युवाओं के हित में 'खेल मैदान त्रिभौनी' में स्टेडियम का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

खेल भवन सह व्यायामशाला की स्थापना

***456 डा. दिलीप कुमार जायसवाल (पूर्णिआ, अररिया स्थानीय प्राधिकार):**

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है प्रत्येक जिला में एक खेल भवन सह व्यायामशाला की स्थापना की योजना तैयार की गई थी परन्तु अबतक यह कार्यान्वित नहीं हो पाया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य की जिला विकास योजना में खेल भवन सह व्यायामशाला को शामिल नहीं किया जाता है और यही कारण है देश के खेल मानचित्र पर यह पिछड़ा हुआ राज्य है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है परन्तु जिला में खेल भवन सह व्यायामशाला नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को सुविधाएं एवं मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक जिला में एक खेल भवन सह व्यायामशाला की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्रधानाध्यापक का पदस्थापन

*457 श्री राजेश कुमार उर्फ बबलु गुप्ता (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत खसरूपुर प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय निर्मलीचक अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का पद रिक्त है, जिस कारण पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में स्थायी प्रधानाध्यापक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुनर्बहाली कबतक

*458 श्री तनवीर अख्तर (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में विगत दो वर्षों के अंतराल में पांच-पांच रजिस्ट्रार की अबतक नियुक्ति की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि सम्प्रति विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति में सेवानिवृत्त वरीय अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को ही किये जाने का प्रावधान है;

(ग) क्या यह सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किये गये सेना/एयरफोर्स के सेवानिवृत्त वरीय अधिकारी को बगैर किसी कारण एवं स्पष्टीकरण के विश्वविद्यालय के द्वारा हटाकर किसी शिक्षक को अनियमित तरीके से रजिस्ट्रार बना दिया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि नियमानुसार रजिस्ट्रार की नियमित नियुक्ति नहीं किये जाने से विश्वविद्यालय का प्रशासनिक ढांचा बिगड़ गया है और इसका असर पठन-पाठन पर भी पड़ रहा है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा में खंड 'ख' में वर्णित अधिकारी की नियमित नियुक्ति करने का

विचार रखती है और पूर्व में नियुक्त किये गये सेना के अधिकारी की पुनर्बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

उत्क्रमण कबतक

*459 श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जिला दरभंगा, अनुमंडल दरभंगा, प्रखंड हनुमान नगर अन्तर्गत बेसिक स्कूल रुपौली घाट में अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय को करीब 5 एकड़ अपनी जमीन है एवं उक्त विद्यालय के आसपास कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं है जिससे बच्चों के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बेसिक स्कूल रुपौली घाट को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मदरसों का अनुदान एवं नियमावली

*460 श्री खालिद अनवर (विधान सभा):

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरकार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के कार्यक्षेत्र के नवीकरण का इरादा रखती है;

(ख) क्या यह सही है कि बोर्ड में स्थगित सैकड़ों मदरसे, जो स्वीकृत हैं, लेकिन उन्हें अनुदान नहीं मिलता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार मदरसा बोर्ड के लिए नियमावली बनाने का इरादा रखती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा स्वीकृत मदरसों को अनुदान देने एवं मदरसा बोर्ड के लिए

नियमावली बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?]
